

क,

डी०एस० गर्बाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2015

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत राजभवन, नैनीताल के जीर्णोद्धार/  
पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 717/IV(2)-श0वि0-12-27(JnNURM)/10, दिनांक 18.05.2012, शासनादेश संख्या: 1539/IV(2)-श0वि0-2013-27(NURM)/10, दिनांक 04.12.2013 एवं शासनादेश संख्या: 1308/IV(2)-श0वि0-2014-27(NURM)/10, दिनांक 26.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार एवं पुर्ननिर्माण परियोजना हेतु कुल ₹572.90 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि परियोजनान्तर्गत अवशेष धनराशि के सापेक्ष ₹300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि ₹300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (iv) कार्यदायी संस्था से मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने पर ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जाए।
- (v) जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (vii) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियन्ता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- (viii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने

...2/-...





से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

- (ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (x) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- (xi) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (xii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
- (xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे ₹234.00 लाख, अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे ₹54.00 लाख तथा अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज